

निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय,

वित्त मंत्रालय और अन्य

बनाम

के.ओ. कृष्णस्वामी

26 अक्टूबर, 1979

[एन.एल. अंतवाल्या, पी.एन. सिंहल और ए.डी. कौशल, जे.जे.]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947- धारा 12(2)(बी) – दायरा  
- आयात लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्यातक द्वारा अधिक चालान  
करना - -यदि धारा 12(2)(बी) का उल्लंघन होता है।

भारत से बाहर वस्तुओं का निर्यात करने वाले निर्यातक को विदेशी  
मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 12 (1) के तहत एक घोषणा  
पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जो यह पुष्टि करता है कि माल का पूरा  
निर्यात मूल्य निर्धारित तरीके से भुगतान किया गया था या किया जाएगा।  
इस धारा की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि उक्त माल को बेचने का  
हकदार कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करेगा या ऐसा कुछ भी करने से  
परहेज नहीं करेगा जिसका यह सुनिश्चित करने का प्रभाव हो। (बी) "माल  
के लिए भुगतान निर्धारित तरीके के अलावा अन्य विवेकपूर्ण तरीके से

किया जाता है या माल के संबंध में विदेशी खरीदार द्वारा देय पूरी राशि का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।"

भारत सरकार द्वारा कपड़ा वस्तुओं और हस्तशिल्प के लिए जारी एक निर्यात संवर्धन योजना में निर्यातकों को केवल निर्यात की गई वस्तुओं के घोषित मूल्य के आधार पर आयात लाइसेंस जारी करने की परिकल्पना की गई थी। आयात लाइसेंस प्राप्त करने पर निर्यातक उन्हें अपने अंकित मूल्य के 200 से 300 प्रतिशत तक के लाभ पर बेचने में सक्षम थे। इसने निर्यातकों को बड़ी हुई राशि के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बाजार या संविदात्मक मूल्य से बहुत अधिक मूल्य दिखाने वाले चालान तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया।

21.97 लाख रुपये के चालान मूल्य के विरुद्ध, अपीलार्थियों में से एक को केवल 1.01 लाख रुपये प्राप्त हुए, जबकि दूसरे अपीलार्थी द्वारा निर्यात किए गए माल के मामले में 17.06 लाख रुपये के चालान मूल्य के खिलाफ वापस भेजी गई राशि 38,000 रुपये थी। दोनों अपीलार्थियों ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोप को स्वीकार कर लिया।

निदेशक ने उन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 12(2) के तहत दोषी पाते हुए उनमें से प्रत्येक पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में उच्च न्यायालय ने इस विचार पर आदेश को अभिखंडित कर दिया कि धारा 12(2)(बी) का उल्लंघन केवल तभी होगा जब विदेशी खरीदार एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा और निर्यातक द्वारा की गई किसी चीज़ के कारण उस राशि या उसके हिस्से का भुगतान नहीं किया गया था और यदि निर्यातक द्वारा माल के संविदात्मक मूल्य का एहसास किया गया था, तो उसे केवल इस तथ्य के कारण किसी भी उल्लंघन का दोषी नहीं ठहराया जा सकता था कि उसने चालान में बढ़ी हुई कीमत दिखाई थी और इस प्रकार आयात लाइसेंस के रूप में अनुचित लाभ प्राप्त किया था।

अपील को खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित किया:** खंड (ख) में आने वाली अभिव्यक्ति "माल के संबंध में विदेशी खरीदार द्वारा देय पूर्ण राशि" का अर्थ केवल वह कुल राशि होगी जो वास्तव में निर्यात की गई वस्तुओं के संबंध में विदेशी खरीदार से देय है, और जो विदेशी खरीदार से देय होगी वह केवल वह कीमत होनी चाहिए जो वह भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, न कि कोई काल्पनिक, गैर-वास्तविक या बढ़ी हुई कीमत जिसे निर्यातक चुन सकता है। किसी भी गलत उद्देश्य के साथ चालान में गलत तरीके से शामिल करें। विदेशी खरीदार को उस कीमत से अधिक और उससे अधिक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है जो उसने प्राप्त माल के लिए भुगतान करने का वादा किया है और इसलिए उस कीमत

और चालान में दी गई कीमत के बीच किसी भी अंतर में उसके द्वारा देय होने का गुण नहीं हो सकता है। यदि सहमत मूल्य का भुगतान निर्यातक को किया गया था, तो खंड (बी) लागू नहीं होता है। [ 1096 एफ-जी]

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2595 और 2596/1969

मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 441 और 44366 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 4-6-1969 से उत्पन्न।

एम.के. बनर्जी, अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल, आर.बी. दातार और गिरीश चन्द्र, अपीलार्थियों की ओर से।

श्यामला पप्पु, विनीत कुमार और ए.के. श्रीवास्तव, प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

**कोशल, न्यायाधिपति.** इस निर्णय के द्वारा हम सिविल अपील संख्या 2595 और 2596/1969 का निस्तारण करेंगे, जिनमें से प्रत्येक में निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार (बाद में 'निदेशक' के रूप में संदर्भित) ने 4 जून 1969 को मैसूर उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा भारत के संविधान के

अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई दो रिट याचिकाओं को अनुमति दी थी।

2. दोनों अपीलों को जन्म देने वाले तथ्यों को संक्षेप में बताया जा सकता है। भारत सरकार ने एक निर्यात प्रोत्साहन योजना शुरू की जिसके तहत कपड़ा वस्तुओं और हस्तशिल्प के निर्यातकों को उनके निर्यात प्रदर्शन के आधार पर कच्चे माल के आयात के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे। इस योजना में केवल निर्यातित वस्तुओं के घोषित मूल्य के आधार पर आयात लाइसेंस जारी करने की परिकल्पना की गई थी। चूंकि निर्यातक ऐसे आयात लाइसेंस की बिक्री से अच्छा लाभ (कुछ मामलों में अंकित मूल्य के 200 से 300 प्रतिशत के बीच) कमाने में सक्षम थे, इस योजना ने कपड़ा निर्यातकों और उनकी ओर से बेनामी कार्य करने वाले दलों की अप्रत्याशित वृद्धि को अस्तित्व में ला दिया। स्थापित निर्यातक, अधिकांश निर्यातकों की विदेश में अपनी शाखाएँ या प्रतिनिधि थे जो भारत से निर्यात किए गए माल के खेप के रूप में कार्य करते थे। आसानी से लाभ कमाने के उद्देश्य से कई निर्यातकों ने बड़ी हुई मात्रा के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्यातित वस्तुओं के मूल्य को बाजार या उसके संविदात्मक मूल्य से कहीं अधिक दिखाने वाले चालान तैयार करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रथा की भनक पाकर प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च, 1965 में मद्रास राज्य के प्रमुख कपड़ा निर्यातकों में से एक के परिसर की आकस्मिक तलाशी ली। इसके परिणामस्वरूप जब्त किए गए दस्तावेज़ और निर्यातक के बयान ने

निदेशालय द्वारा पहले प्राप्त जानकारी की पुष्टि की। परिणामस्वरूप, मद्रास राज्य के लगभग सभी कपड़ा और हस्तशिल्प निर्यातकों को नोटिस जारी किए गए, जिसमें उनसे भारत के बाहर विभिन्न पार्टियों को निर्यात किए गए माल की कीमत के रूप में उनके द्वारा प्रस्तुत चालान में दिखाई गई पूरी राशि को न वसूलने का कारण बताने के लिए कहा गया। ऐसे दो निर्यातक थे मेसर्स के.ओ.कृष्णास्वामी (सिविल अपील संख्या 2595/1969 में प्रतिवादी) और मेसर्स नागराजा विदेशी व्यापारी (सिविल अपील संख्या 2596/1969 में प्रतिवादी) और निदेशक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 19(2) के तहत उनके खिलाफ की गई कार्यवाही से पता चला कि उनके बीच नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उन्होंने सिंगापुर और अन्य स्थानों पर कपड़ा सामान और हस्तशिल्प की 53 खेपों का निर्यात किया था:

नाम	निर्यात मूल्य जैसा जी.आर. 1 फॉर्म में दर्शित है	नौ परिवहन की संख्या	प्रत्यावर्तित राशि	भुगतान योग्य राशि
1.मैसर्स के. ओ.कृष्णास्वामी	21,97,046.62	31	1,01,165.70	20,95,880.92
2.मैसर्स नागराजा ओवरसीज ट्रेडर्स	17,06,159.00	22	38,510.25	16,67,648.75

निदेशक इस निष्कर्ष पर पहुंचा :

“उपरोक्त कथन से, यह स्पष्ट हो जाएगा कि, पहली दो फर्मों के संबंध में, जानबूझकर ओवर-इनवॉइसिंग के कारण बकाया (जो कि अस्तित्वहीन है) और इसलिए गैर-प्रत्यावर्तनीय के रूप में दिखाई गई कुल राशि 37,63,529.67 रुपये है। “

उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल, 1965 के अपने इकबालिया बयान (उन्हें दिए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिए गए) और सुनवाई में उनकी दलीलों में, दोनों फर्मों ने "अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों" के लिए दोषी ठहराया था। अधिनियम की धारा 12(2) के तहत दोनों को दोषी पाते हुए, निदेशक ने 27 मई, 1965 के अपने आदेश द्वारा, उनमें से प्रत्येक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और यह वह आदेश था जो दोनों में से प्रत्येक पर लगाया गया था। दोषी फर्मों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में अवैध बताया गया।

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दोनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि ई. सी. ओ. द्वारा पाए गए तथ्यों पर, धारा 12 की उप-धारा (2) के तहत कोई अपराध नहीं है: बनाया गया। उस खंड के प्रासंगिक भाग का पुनरुत्पादन किया जाता है:-

"12(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सभी वस्तुओं या किसी भी सामान या अधिसूचना में निर्दिष्ट वस्तुओं के वर्ग को भूमि, समुद्र या वायु (इसके बाद

इस खंड में निर्यात के रूप में संदर्भित) द्वारा ले जाने या भेजने पर रोक लगा सकती है। भारत में इस प्रकार निर्दिष्ट किसी भी स्थान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जब तक कि निर्यातक निर्धारित प्राधिकारी को ऐसे साक्ष्य द्वारा समर्थित निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा प्रस्तुत नहीं करता है जो निर्धारित या निर्दिष्ट किया जा सकता है और सभी भौतिक विवरणों में सत्य है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, प्रतिनिधित्व करने वाली राशि भी शामिल होगी -

(i) माल का पूर्ण निर्यात मूल्य; या

(ii) यदि निर्यात के समय माल का पूर्ण निर्यात मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो वह मूल्य जो निर्यातक, मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान माल की बिक्री पर प्राप्त करने की उम्मीद करता है;

और उक्त घोषणा में पुष्टि करता है कि माल का पूरा निर्यात मूल्य (चाहे निर्यात के समय पता लगाया जा सके या नहीं) निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित तरीके से भुगतान किया गया है या किया जाएगा।



(2) जहां माल का कोई निर्यात किया गया है, जिस पर उपधारा (1) के तहत एक अधिसूचना लागू होती है, कोई भी व्यक्ति उक्त माल को बेचने या खरीदने का हकदार नहीं है, रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना, ऐसा नहीं करेगा या नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी करने या करने से या ऐसा कोई भी कार्य करने से बचना जिसका यह सुनिश्चित करने का प्रभाव हो-

(क) माल की बिक्री में इस हद तक देरी होती है जो व्यापार के सामान्य प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अनुचित है, या

(ख) माल के लिए भुगतान निर्धारित तरीके से अन्यथा किया जाता है या माल के संबंध में विदेशी खरीदार द्वारा देय पूरी राशि का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ऐसी कटौतियों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी जा सकती है, या उपर्युक्त सीमा तक विलंबित है:

बशर्ते कि इस उप-धारा के किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई कार्यवाही तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारित अवधि समाप्त न हो गई हो और उपरोक्त पूरी राशि का प्रतिनिधित्व करने वाले माल का भुगतान निर्धारित तरीके से नहीं किया गया हो।“

उच्च न्यायालय के समक्ष निदेशक की ओर से तर्क दिया गया कि दोनों कंपनियां निर्यात किए गए माल की कीमत का "ओवर-इनवॉइसिंग" करके कार्रवाई करने की दोषी थीं, जिसका प्रभाव यह सुनिश्चित करने में था कि निर्यात किए गए माल के लिए भुगतान नहीं किया गया था। विदेशी खरीदार द्वारा उसके संबंध में देय पूरी राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए उन्होंने अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) के खंड (बी) का उल्लंघन किया है। 27 मई, 1965 के अपने आदेश में निदेशक द्वारा निकाले गए निष्कर्षों और धारा 12 की उप-धारा (2) की सभी सामग्रियों की पूरी चर्चा के बाद उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया था। उसकी राय थी कि उक्त खंड (बी) का उल्लंघन तभी किया जाएगा जब विदेशी खरीदार बाध्य हो एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए और निर्यातक द्वारा किए गए किसी कार्य के परिणामस्वरूप उस राशि या उसके एक हिस्से का भुगतान नहीं किया गया था और यदि निर्यातक द्वारा माल का संविदात्मक मूल्य प्राप्त कर लिया गया था तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। ऐसा कोई भी उल्लंघन केवल इस तथ्य के कारण है कि उसने चालान में बढ़ी हुई कीमत दिखाई थी और इस प्रकार चालान की गई राशि के लिए आयात लाइसेंस के रूप में अवांछित लाभ प्राप्त किया था। इसलिए हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाएं स्वीकार करते हुए निदेशक के 27 मई 1965 के आदेश को रद्द कर दिया।

3. उच्च न्यायालय के समक्ष निदेशक की ओर से दिए गए तर्क को हमारे सामने दोहराया गया है, और दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद हमारी स्पष्ट राय है कि धारा 12 की उप-धारा (2) पर दी गई व्याख्या उच्च न्यायालय अपवादहीन है. अभिव्यक्ति "पूरी राशि देय माल के संबंध में विदेशी खरीदार द्वारा" खंड (बी) में होने वाली कुल राशि का मतलब केवल कुल राशि होगी जो वास्तव में निर्यात किए गए माल के संबंध में विदेशी खरीदार से देय है; और एक विदेशी खरीदार से जो देय होगा वह केवल वह कीमत होगी जिसे वह भुगतान करने के लिए सहमत हुआ है, न कि कोई काल्पनिक, अवास्तविक या बढ़ी हुई कीमत जिसे निर्यातक किसी भी गुप्त उद्देश्य के साथ चालान में गलत तरीके से शामिल करना चुन सकता है। किसी भी हद तक, विदेशी खरीदार को उस कीमत से अधिक किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जो उसने प्राप्त माल के लिए भुगतान करने का वादा किया है और उस कीमत और चालान में दी गई कीमत के बीच कोई अंतर है। इसलिए उसके द्वारा 'देय' बनने का गुण नहीं हो सकता। और यदि ऐसा है और निर्यातक को वास्तव में सहमत कीमत का भुगतान कर दिया गया है, तो खंड (बी) बाद के मामले में लागू नहीं होता है।

4. धारा 12 की उप-धारा (1) इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्यातक के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी घोषणा में माल का पूर्ण (और सही) निर्यात मूल्य निर्दिष्ट करे, लेकिन फिर इस अधिदेश का उल्लंघन उप-धारा

अपनाए गए उल्लंघनों द्वारा कवर नहीं किया जाता है। -धारा 2)। ऐसा हो सकता है कि प्रतिवादी-फर्मों द्वारा निर्यात किए गए माल के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत चालान में की गई झूठी घोषणाएं उन्हें देश के दंड कानून के कुछ प्रावधानों (अधिनियम की धारा 12(2) के अलावा) के तहत उत्तरदायी बनाती हैं। लेकिन यह मामले का एक पहलू है जिससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है।

5. परिणामस्वरूप अपील विफल हो जाती हैं और खारिज की जाती हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

पीबीआर.

अपीलें खारिज की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

**अस्वीकरण-** इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

\*\*\*\*\*